



## पंचायती राज संस्थाओं का वनियिमन

- **राज्य का वषिय:** स्थानीय शासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तथा पंचायती राज संस्थाएँ संबंधित राज्य पंचायती राज अधनियिमों के अनुसार कार्य करती हैं ।
- **संवधानकि ढाँचा:**
  - 73वें संवधान संशोधन अधनियिम (1992) द्वारा त्रसितरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई जिसमे महिलाओं के लिये 1/3 आरक्षण अनविर्य कया गया, जिसि बाद में 21 राज्यों और 2 केंद्रशासति प्रदेशों में बढाकर 50% कर दया गया ।
  - अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचति जातयिों, अनुसूचति जनजातयिों और पछिडे वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है ।
  - संवधान का अनुच्छेद 40, जो राज्य के नीतनरिदेशक सदिधांत है, राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तयिों और प्राधकिार का अधिकार प्रदान करता है ।
- पंचायतों (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियिम, 1996, अनुसूचति क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतकि संसाधनों के प्रबंधन और जनजातीय संस्कृति एवं आजीवकि की रक्षा के लिये वशिष शक्तयिों प्रदान करता है ।

?????? ???? ???? ????:

प्रश्न: 'प्रधान पति' की प्रथा 73वें संवधान संशोधन के उद्देश्यों को कसि प्रकार प्रभावति करती है? पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ ।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लिये नरितर चुनौतयिों क्या हैं? (2019)

प्रश्न. वविधिता, समानता और समावेश सुनशिचति करने के लिये उच्च न्यायपालकिा में महिलाओं के अधकि प्रतनिधितिव की वांछनीयता पर चर्चा कीजयिे । (2021)